सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

16-31 अगस्त, 2023 वर्ष-1 अंक-10

निःशुल्क प्रति

देश के रक्षक बने

पर्यावरण के पहरेदार

गृह मंत्रालय का अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान बना पर्यावरण संरक्षण का महाकुंभ

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

गांधीनगर में बढ़ रहा है हरित क्षेत्र	11
सबकी भागीदारी से लक्ष्य की प्राप्ति	13
पूरी दुनिया को दिया पर्यावरण संरक्षण का मंत्र	14
अपनी संस्कृति से पहुंचे विरासत तक	16
सबकी सहभागिता 'अमृत वाटिका'	20
राष्ट्र सेवा में जीवन समर्पित	21
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का डंका	23
सेवा के जरिए संकल्प सिद्धि	25

विशेष रिपोर्ट

05 देश के रक्षक बने पर्यावरण के पहरेदार

09 गृह मंत्रालय का अखिल भारतीय वृक्षारोपण...

18 नए भारत का नया मुकाम

संपादक की कलम से...

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

> केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य तय किया है। अब तक चार करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इसे पर्यावरण संरक्षण का एक महाकुंभ बताया है।

आज का युग पर्यावरणीय चेतना का युग है। हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति चिंतित है जिसके निवारण के लिए सभी की भागीदारी अहम है। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्ययोजना बनाती है, उसे सभी मिलकर व्यवहार में लाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय देश में 'अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान' को हर घर तक पहुंचा रहा है, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता भी बढ़ रही है। इस अभियान के तहत अब तक 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। चार करोड़वां पौधा स्वयं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने लगाया। उन्होंने देश भर में 5 करोड़ वृक्ष लगाने के 'अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान' को पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में एक महाकुंभ की तरह बताया है।

माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की 𝕏 (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे शानदार उपलब्धि बताया और कहा कि पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में गृह मंत्रालय का यह वृक्षारोपण अभियान हर किसी को प्रेरित करने वाला है।

बीते दशक में सरकार की प्राथमिकता में वृक्षारोपण भी प्रमुखता से शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इसको लेकर कई बार बात की। कभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो कई बार मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान को कार्यक्रम में जगह मिली। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान को विशेष तौर पर सराहा।

देश के अधिकतर हिस्सों में अब केवल पर्यावरण दिवस पर ही नहीं, बल्कि जन्मदिन सहित पर्व-त्यौहारों के अवसर पर भी वृक्षारोपण का सिलसिला शुरू हो गया है। विभिन्न आयोजनों में स्वागत के क्रम में पौधा देने का चलन बढ़ता जा रहा है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो भी अपने आयोजनों में आदरस्वरूप आगत अतिथियों का स्वागत पौधा देकर कर रहा है।

'सजग भारत' के इस अंक में हमने विशेष रूप से पर्यावरण और वृक्षारोपण पर बात की है। मेरे विचार से पर्यावरण संरक्षण का दायित्व हर नागरिक का है। हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अगली पीढ़ी के लिए पौधे लगाएं। हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है, हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारा ई-मेल है : sajag-bharat@bprd.nic.in

जय हिंद!

पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में गृह मंत्रालय का यह वृक्षारोपण अभियान हर किसी को प्रेरित करने वाला है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

गृह मंत्रालय के 'अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान' के तहत 4 करोड़वां पौधा लगाया। देश की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा वाले इस अभियान को सफल बनाने में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय हैं।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

रक्षाबंधन के अवसर पर सशस्त्र सीमा बल फ्रंटियर, पटना की बहनों और भाइयों के साथ रक्षाबंधन मनाया। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के आईजी पंकज दारद जी, डीआईजी विक्रम जी, कमांडेंट जितेंद्र सिंह जी, उप कमांडेंट श्री अजीत सिंह जी, डॉ. सुधांशु जी एवं सशस्त्र सीमा बल के पदाधिकारी रहे।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

मंज़िलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो, फासला क्या है 'इसरो' के सभी वैज्ञानिकों को चाँद तक के सफर की हार्दिक शुभकामनाएं।

श्री निशीथ प्रमाणिक
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री

59 साल, 50 करोड़+ बैंक खाते! वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने एवं देशवासियों के सशक्तिकरण करने हेतु उल्लेखनीय पहल साबित हो रही जन धन योजना।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2023 के समापन पर गृहमंत्री श्री अमित शाह ने पुलिस नेतृत्व से एक ऐसी आपराधिक न्यायिक व्यवस्था की रचना करने को कहा जो नए कानूनों पर आधारित हो, जिसमें नई तकनीक का समावेश, फॉरेंसिक का उपयोग हो और नागरिकों को संवैधानिक अधिकार व त्वरित न्याय मिल सके।

गृह मंत्रालय
भारत सरकार

गृह मंत्रालय का अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान

देश के रक्षक बने पर्यावरण के पहरेदार

ब्यूरो

हाल के वर्षों में पूरी दुनिया ने जलवायु परिवर्तन के दंश को झेला है। प्राकृतिक आपदाओं ने मानव को सचेत किया है कि पर्यावरण संरक्षण पर वह पहले से अधिक ध्यान दें। पर्यावरण और पारिस्थितिकि के साथ खिलवाड़ न करें। जैसे-जैसे दुनिया जलवायु परिवर्तन की तात्कालिकता से जूझ रही है, तो भारत एक हरित राष्ट्र बनने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि देश के स्वच्छ और हरित मिशन को बढ़ावा मिले। इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के सहयोग से वृक्षारोपण का लक्ष्य तैयार किया। इसके तहत पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तैयार किया गया। इसके लिए सीएपीएफ की खाली जमीन पर पेड़ लगाने का काम सौंपा गया है, जिनमें से 50 प्रतिशत पौधों का जीवन 150-200 साल का होना चाहिए और बाकी 50 प्रतिशत पौधों का तेजी से विकास होना चाहिए और उनका जीवन काल 10 साल से कम नहीं होना चाहिए। यह अभियान प्रति वर्ष एक करोड़ पेड़ों के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था और यह पर्यावरण सुरक्षा के प्रति आंतरिक सुरक्षा में शामिल बलों की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किए गए अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और अधिकारियों की भागीदारी प्रशंसनीय है। जो देश के रक्षक रहे हैं, वे आगे आकर पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण का काम कर रहे हैं। व्यापक

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का विजन

वृक्षों की मानव जीवन में महत्ता को दर्शाने वाले 'मत्स्य पुराण' के सूत्र को अभियान का मूल मंत्र बनाया गया जिससे कि बल कर्मियों और उनके माध्यम से समाज में वृक्षों के प्रति संवेदनशीलता और चेतना जाग्रत हो।

दशकूपसमा वापी, दशवापीसमो ह्रदः। दशह्रदसमो पुत्रो, दशपुत्रसमो द्रुमः।।

(एक जलकुंड दस कुएं के समान है, एक तालाब दस जलकुंडों के बराबर है, एक पुत्र का दस तालाबों जितना महत्व है और एक वृक्ष का दस पुत्रों के समान महत्व है।)

12 जुलाई, 2020 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर, गुरुग्राम में अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेकर पीपल का पौधा लगाया। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि मैं हमारे सशस्त्र बलों के वीर जवानों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं, जो देश की रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करने वाले इस विशाल अभियान के माध्यम से देशभर में 1.37 करोड़ से अधिक लंबी आयु वाले वृक्षों के पौधे लगा रहे हैं। उन्होंने सभी जवानों से अपील की कि जब तक लगाने वाले व्यक्ति से वृक्ष बड़ा न हो जाए तब तक उसका ध्यान रखा जाए, उसके बाद वह वृक्ष पीढ़ियों तक हमारा ध्यान रखेंगे। आक्सीजन देने की क्षमता, मौसम की अनुकूलता और आयु को ध्यान में रखते हुए इस महाअभियान के लिए पीपल, जामुन, नीम, वट और बरगद जैसे पेड़ों का चयन किया गया है।

पौधरोपण अभियानों के सफल संचालन के माध्यम से, देश अधिक टिकाऊ भविष्य के बीज बो रहा है। हमारे पूर्वजों ने जो पौधे लगाए, उस वृक्ष का अब हम लाभ उठा रहे हैं। सभी नागरिक अब जो पौधा लगाएंगे, उसका लाभ आने वाली पीढ़ी उठाएगी। इस प्रयास का न केवल देश के भीतर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह अपने वन और वृक्ष आवरण के विस्तार के लिए भारत की प्रतिबद्धता का एक मजबूत संकेतक भी है, जिसका लक्ष्य पारिस्थितिकि जिम्मेदारी में एक वैश्विक उदाहरण स्थापित करना है। उल्लेखनीय है कि श्री शाह ने 12 जुलाई 2020 को इस व्यापक, मानवीय और अनूठे वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया था। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने वर्ष 2020 से 2022 तक केवल तीन वर्ष के छोटे अंतराल में पूरे देश में सामूहिक रूप से 3.55 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इस अभियान के तहत कुल वृक्षारोपण की संख्या पांच करोड़ हो जाएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति समग्र राष्ट्र के प्रयासों में सीआरपीएफ के अनुकरणीय योगदान को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के अभियान को सराहा

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गृह मंत्रालय के पांच करोड़ वृक्षारोपण के अभियान को सराहना मिली है। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में गृह मंत्रालय का यह वृक्षारोपण अभियान हर किसी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर की और इसके लिए अलग से विभाग बनाया गया। साल 2021 में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में अखिल भारतीय वृक्षारोपण मिशन-2021 के तहत एक करोड़वां वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी आजादी के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को महत्व दिया था। वृक्षारोपण महाअभियान भारत की धरा को हरा-भरा बनाने के प्रयास के अलावा यह भी दर्शाता है कि केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल न केवल राष्ट्र की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा बल्कि इसके पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति भी कृतसंकल्प है।

शानदार उपलब्धि! पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण की दिशा में गृह मंत्रालय का यह वृक्षारोपण अभियान हर किसी को प्रेरित करने वाला है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के तीन बीघा कॉरीडोर में वृक्षारोपण किया

किबिथू अरुणाचल प्रदेश में वृक्षारोपण करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह असम के गुवाहाटी में वृक्षारोपण करते हुए

किशनगंज बिहार में वृक्षारोपण करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

जम्मू कश्मीर के लेथेपुर में वृक्षारोपण करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

कैसे अलग है यह अभियान

गृह मंत्रालय द्वारा पांच करोड़ वृक्षारोपण का यह अभियान अन्य वृक्षारोपण अभियानों से बिल्कुल ही अलग है। श्री अमित शाह का मानना है कि हमें प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करना चाहिए शोषण नहीं। अंधाधुंध विकास के कारण दुनिया के पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचा है। ग्लोबल वॉर्मिंग और क्लाइमेट चेंज ऐसे दो खतरे बने हैं, जो हर देश के दुश्मन हैं। भारी बारिश, अकाल, भूस्खलन अब काफी संख्या में सामने आ रहे हैं और इनका मूल कारण जलवायु परिवर्तन है। केंद्रीय गृह मंत्री जी के निर्देश पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशकों को कहा गया है कि अभियान के दौरान रोपित पौधों के विकास की समीक्षा नियमित रूप से करें। साथ ही जवान यह सुनिश्चित करें कि जो वृक्ष वो लगा रहे हैं उस वृक्ष की लंबाई जवान की लंबाई के बराबर नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल करें।

इस अभियान में केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा रोपित वृक्षों के स्वस्थ विकास की जिम्मेदारी संबंधित कमांडिग ऑफिसरों को सौंपी गई, जिसकी नियमित जानकारी वे स्वयं लेते हैं। नोडल अधिकारी के रूप में एडीजी रैंक का एक अधिकारी और नोडल अधिकारी के रूप में सहायक कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी वृक्षारोपण अभियान का जायजा ले रहे हैं और संबंधित डीजी के साथ अपनी स्थिति

केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा वृक्षारोपण

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ अपने भविष्य के कार्यों में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण को समावेशित रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं। पिछले साल में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, असम राइफल्स आदि के जवानों द्वारा 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अर्धसैनिक बलों द्वारा वृक्षारोपण अभियान हरित पहल के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ पहल में भारत को विश्व नेता बनाने के प्रयासों के साथ अच्छी तरह से फिट बैठता है।

> एक वृक्ष को बड़ा होते देखने से लेकर उसे सींचने और उसकी देखभाल करने के प्रयासों के बाद जब वो छाया देने लगता है और वातावरण को शुद्ध करने लगता है। उसका कोई माप नहीं है। वृक्ष लगाना सरकार का कार्यक्रम है, उसको जीवित रखना, बड़ा करना और एक पौधे को वृक्ष में परिवर्तित करना सीएपीएफ जवान का कार्यक्रम होना चाहिए।
>
> **श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

साझा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर के सीआरपीएफ और सीएपीएफ के जवानों से स्वयं को एक वृक्ष के साथ जोड़ने का आह्वान किया और कहा कि अगर आप खुद को एक वृक्ष के साथ जोड़ लेंगे तो आपको उससे लगाव हो जाएगा, जो आपको आत्मसंतुष्टि देगा, तनाव कम करेगा और जीवन जीने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण भी देगा। क्योंकि सृजन ही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा और कला है। विकास की गति के साथ-साथ ग्लोबल वॉर्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चिंता को व्यवस्था में ही शामिल करना होगा और उसका सबसे सरल रास्ता है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और उत्सर्जित कार्बन की व्यवस्था करना और इसका एक ही रास्ता है कि वृक्षों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तभी ऑक्सीजन मिलती रहेगी और ओजोन की परत सुरक्षित रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कई महकमे वृक्षारोपण को प्रमुखता से अपना रहे हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के मुख्यालय में बिरसा मुंडा उद्यान में समय-समय पर अधिकारियों-कर्मियों द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। साथ ही ब्यूरो अपने आनुषांगिक इकाइयों को भी इसके लिए लगातार प्रेरित कर रहा है।■

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा वर्ष 2020, 2021, 2022 एवं 2023 के दौरान किये गए वृक्षारोपण का विवरण

क्र. सं.	बल का नाम	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023 (31 अगस्त तक)
1	असम राईफल्स	76,42,484	31,08,186	21,15,103	7,52,966
2	बी.एस.एफ	11,82,379	20,06,589	25,00,000	7,85,651
3	सी.आई.एस.एफ	8,98,656	8,06,986	5,36,719	4,90,760
4	सी.आर.पी.एफ	27,87,615	24,03,441	25,30,232	19,53,524
5	आई.टी.बी.पी	5,45,652	10,21,984	6,07,672	4,92,469
6	एन.एस.जी	2,59,969	1,03,817	3,00,100	1,95,592
7	एस.एस.बी	14,21,285	12,70,242	10,33,699	12,18,489
	कुल योग	1,47,38,040	1,07,21,245	96,23,525	58,89,451

- वृक्षारोपण अभियान-2023 के अंतर्गत 18 अगस्त, 2023 को ग्रुप केन्द्र, सीआरपीएफ, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने भाग लिया एवं पीपल का पौधा लगाया।
- 18 अगस्त, 2023 को सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, असम राईफल्स एवं एनएसजी द्वारा अपने कैम्पसों/परिसरों में 11,15,557 पौधे लगाये गये।
- 31 अगस्त, 2023 तक कुल 4,14,73,069 पौधे लगाये जा चुके हैं।

गृह मंत्रालय का अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान बना पर्यावरण संरक्षण का महाकुंभ

- **18 अगस्त, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने चार करोड़वां पौधा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में लगाया।**
- **केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के तहत पांच करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया है।**

ब्यूरो

गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वृक्षारोपण अभियान आज पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज देश भर में इस अभियान को जहां सराहना मिल रही है वहीं बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ भी रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में चार करोड़वां पौधा लगाने के बाद केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने उस दिन को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि वृक्ष लगाना सरकार का कार्यक्रम है, उसको जीवित रखना, बड़ा करना और एक पौधे को वृक्ष में परिवर्तित करना सीएपीएफ जवान का कार्यक्रम होना चाहिए।

चार करोड़वें पौधे के रूप में पीपल का पौधा लगाने के बाद श्री शाह ने कहा 'हम बहुत जल्द ही 5 करोड़ वृक्ष रोपित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।' उन्होंने बताया कि तीन साल पहले यह तय किया गया था कि दिसंबर, 2023 से पहले पांच करोड़ वृक्ष लगाएंगे और गैप फिलिंग के बाद इन्हें बड़ा कर दुनिया को समर्पित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों पर विश्वास जताया कि दिसंबर 2023 तक पांच करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और सीमाओं पर स्थित प्रथम गाँवों में जन सुविधाएं पहुँचाने के साथ-साथ अब सीएपीएफ वृक्षारोपण अभियान से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं हों या फिर कोरोना जैसी महामारी, हमारे सीएपीएफ ने अपनी जान की परवाह किए बिना जनता पर आए हर संकट में साथ खड़े रहने का जज्बा दिखाया है। श्री शाह ने कहा कि ये विश्व में सुरक्षा के साथ जुड़ी एजेंसियों के पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

खास बात यह है कि इस वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत जलवायु के

देश के विभिन्न भागों में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया वृक्षारोपण

तारीख	स्थान	वृक्ष का नाम
1 मार्च, 2020	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	आम
12 जुलाई, 2020	गुरुग्राम, हरियाणा	पीपल
25 जुलाई 2021	सोहरा, चेरापूंजी, मेघालय	चिनार का पेड़
17 सितंबर 2021	मुखेड़, नांदेड़, महाराष्ट्र	पीपल
26 अक्टूबर 2021	लेथपोर, जम्मू एवं कश्मीर	रुद्राक्ष
6 मई 2022	तीन बीघा कॉरिडोर कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	आम
24 सितंबर, 2022	किशनगंज, बिहार	नीम
10 अप्रैल, 2023	किबिथू, अरुणाचल प्रदेश	संतरा
18 अगस्त, 2023	नोएडा, उत्तर प्रदेश	पीपल

अनुरूप ईकाइवार लगाए जाने वाले पौधों की संख्या और प्रजातियों का आंकलन किया गया और इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई। साथ ही यह भी निश्चित किया गया कि लगाए जाने वाले पौधे यथा संभव देसी प्रजातियों के हों और लंबी आयु के हों। पौधों की प्रजातियों के चयन में यह भी ध्यान रखा गया कि वे आरोग्यवर्धक और पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी हों। कई महत्वपूर्ण अवसरों पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने खुद पौधा लगाया और लोगों से भी इस व्यवहार को अपनाने के लिए कहा है। श्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान 'वृक्षम रक्षति रक्षितः' का जाप किया, जिसका अर्थ है, अगर हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, तो पर्यावरण हमारी रक्षा करेगा। उनका कहना था कि यदि पेड़ों की देखभाल नहीं की गई, तो पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उपनिषदों में भी वृक्षों को श्रद्धा और आदर के साथ महिमा मंडित किया गया है। श्री शाह का कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत को कई क्षेत्रों में विकसित और आत्मनिर्भर बनाकर दुनिया में भारत का स्थान मजबूत करने का काम किया है। हमारी धरोहर और संस्कृति ने हमेशा पर्यावरण सुरक्षा के लिए काम किया है और हमने भावनाओं और कर्म से हमेशा पर्यावरण की सुरक्षा की है। प्रधानमंत्री ने ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में भारत को अगुआ बनाने का काम किया है।

वृक्षारोपण अभियान केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों तक ही सीमित नहीं है, यह उनका पारिवारिक प्रयास भी बन गया है। परिवार के सदस्यों ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इस पवित्र लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे भी जुट गए हैं। प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लगाए गए पौधों की वृद्धि और देखभाल की जिम्मेदारी कमांडिंग अधिकारियों को दी गई, जो उनके बारे में अद्यतन जानकारी लेते रहते हैं। मंत्रालय की ओर से पौधे लगाते समय दो चीजों का ख्याल रखा गया है। एक, पौधे लंबी आयु वाले हों और दूसरी, पीपल, बरगद, नीम, जामुन आदि जैसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधा लगाया जाए। इस प्रकार के सभी वृक्ष 100 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले हैं। ■

गांधीनगर में बढ़ रहा है हरित क्षेत्र

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और गांधी नगर से सांसद श्री अमित शाह की पहल पर बदल गई इस क्षेत्र की आबोहवा

ब्यूरो

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से देश भर में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान से गुजरात का गांधीनगर क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और गांधीनगर से सांसद श्री अमित शाह की पहल पर इस क्षेत्र की आबोहवा बदल गई है। केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयास से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सूखे हुए पौधों के प्रतिस्थापन, वृक्षारोपण में आंगनबाड़ी, स्कूलों और आवास समितियों को शामिल करने और लोकसभा क्षेत्र में सभी प्रवेश सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कर विशिष्ट पहचान देने पर विशेष जोर दिया गया है।

गांधीनगर से सांसद बनने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इस क्षेत्र में बहुत कुछ बदला है। उन्होंने गांधीनगर लोकसभा को हरियाली लोकसभा बनाने का नारा दिया। इतना नहीं इसके लिए वृक्षारोपण पर भी विशेष जोर दिया है। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने और हरित क्षेत्र बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा प्रशासन, सरकारी कार्यालयों, हाउसिंग सोसाइटियों, पंचायतों, निगमों और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से कई वृक्षारोपण अभियान शुरू किए गए। 'मिशन मिलियन ट्री' एक मिसाल है। इसे 2019-20 में शुरू किया गया। इसके तहत अहमदाबाद नगर निगम ने 24 लाख से अधिक पेड़ और पौधे लगाए हैं, 15 उद्यान विकसित किए गए हैं और 53 स्थानों पर शहरी वन (जापानी मियावाकी तकनीक का उपयोग करके बनाए गए 8 ऑक्सीजन पार्क सहित) शुरू किए गए हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह पहल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई।

गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए गृहमंत्री ने जमीन से जुड़कर काम किया है। क्षेत्र में रोपे गए वृक्षों में से 70 प्रतिशत आज भी हरियाली का दायरा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। साल 2023-24 तक गृह मंत्री के निर्देश पर सूखे हुए पौधों के प्रतिस्थापन, वृक्षारोपण में आंगनबाड़ी, स्कूलों और आवासीय समितियों को शामिल करने और लोक सभा क्षेत्र के सभी प्रवेश सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कर विशिष्ट

आंकड़ें दे रहे गवाही

- गांधीनगर जिले में वर्ष 2014-19 के दौरान वन विभाग के अंतर्गत क्षेत्र में वृक्ष घनत्व 59.19 (प्रति हेक्टेयर पेड़) था। यह 2019-2023 के दौरान बढ़कर 64.03 (प्रति हेक्टेयर पेड़) हो गया।
- 2023-24 में अनुमानित कुल 16.40 लाख पौधे नि:शुल्क वितरित किए गए।
- वन विभाग द्वारा 2019-20 से 2023-24 तक पिछले 5 वर्षों में कलोल तालुका में कुल 477 हेक्टेयर और गांधीनगर तालुका में कुल 374 हेक्टेयर, कुल 851 हेक्टेयर में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया और कुल 7,31,695 पौधे लगाए गए।
- 2023-24 में कलोल और गांधीनगर तालुका में कुल 317 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया जिसमें कुल 3,14,741 पौधे लगाए गए, जो उपरोक्त पांच साल के आंकड़ों में शामिल है।
- 2022-23 और 2023-24 में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कलोल और गांधीनगर तालुका से गुजरने वाली कुल 12 सड़कों के किनारे कुल 13200 पौधे लगाए गए हैं।

गुजरात का गांधीनगर हरियाली का पर्याय बन कर उभरा है। वन विभाग की तरफ से सामाजिक वानिकी के अंतर्गत चलाये गये वृक्षारोपण अभियान ने इस जिले की तस्वीर बदल दी है। यह काम कृषि वानिकी योजना के विभिन्न मॉडलों के अंतर्गत किसानों के खेत में वृक्षारोपण के जरिए किया जाता है। 2023-24 में नए वन आवरण मॉडल के तहत गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के एक लाख पौधे लगाए गए हैं।

गांधीनगर में हो रहा है तालाबों का जीर्णोद्धार

पहचान देने पर विशेष जोर दिया गया है। दोनों जिले के वन विभाग, अहमदाबाद नगर निगम, गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के सामूहिक प्रयास से इस वर्ष गांधीनगर लोक सभा क्षेत्र में 28 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

गांधीनगर में दो वर्ष पूर्व वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने वृक्षों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा,'यदि हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण हमारा ध्यान रखेगा। इस प्राचीनतम भारतीय संस्कृति की सीख को श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यों, नीतियों और अपने परिश्रम से प्रतिस्थापित किया है। हमारे उपनिषदों में भी कई जगहों पर वृक्षों का महात्म्य किया गया है।' श्री शाह ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम छोटे पैमाने पर है लेकिन इसका प्रभाव और परिणाम इतना व्यापक है कि यह आने वाली कई पीढ़ियों को स्वस्थ और लंबा जीवन प्रदान करता है। यदि पेड़ों की देखभाल नहीं की गई तो पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

श्री शाह ने इस अवसर पर कहा था कि अहमदाबाद को सिर्फ भारत ही नहीं, विश्वभर का सबसे अधिक ग्रीन कवरेज वाला शहर बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए और यह संभव भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे वृक्ष लगाने का प्रयास होना चाहिए जो तीन-चार पीढ़ियों तक आक्सीजन प्रदान कर सकें। हरियाली का महत्व समझने के लिए सोच व्यापक होनी चाहिए। सोचिए हम सभी काम में व्यस्त होते रहे, गगनचुंबी इमारतें बनती रहें और जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या होगा। सांस लेना मुश्किल होगा और ऐसे में जिंदगी की कल्पना करना ही डरवाना माहौल पैदा कर देगा। शायद ही कोई आम इंसान इस ओर सोच पाया है।

आंकड़ें बताते हैं कि अहमदाबाद जिले के साणंद और बावला तालुका में पिछले पांच वर्षों में वन विभाग ने विभागीय एवं सक्रिय जनभागीदारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत सक्रिय वृक्षारोपण कार्य किए। वर्ष 2017 में बावला और साणंद तालुका में वृक्ष घनत्व 7.98 प्रति हेक्टेयर था जो कि वर्ष 2021 में की गई गणना में बढ़कर बावला में 10.28 प्रति हेक्टेयर और साणंद में 13.54 प्रति हेक्टेयर हो गया।

वन विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में 2019-20 से 2023-24 तक, साणंद तालुका में कुल 503 हेक्टेयर तथा बावला तालुका में 426 हेक्टेयर कुल 929 हेक्टेयर में विभिन्न योजनाओं के तहत वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जिसमें चालू वर्ष 2023-24 में साणंद और बावला तालुका में कुल 232 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। यह कार्यवाही पंचायत भूमि, सरकारी भवनों, किसान के खेत तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर की जाती है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अहमदाबाद जिले के साणंद और बावला तालुका से गुजरने वाली कुल 9 सड़कों पर सड़क किनारे कुल 17,350 पौधे लगाए गए हैं। चालू वर्ष में, साणंद तालुका में एक वन क्षेत्र तैयार किया गया है जिसमें एक हेक्टेयर में लगभग 10,000 पौधे लगाए गए हैं। ■

सबकी भागीदारी से लक्ष्य की प्राप्ति

ब्यूरो

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के साथ-साथ अपने भविष्य के कार्यों में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण को समावेशित रखने के अपने दृढ़ संकल्प को दोहराते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन से प्रेरित और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने वर्ष 2020 से 2022 तक केवल तीन वर्ष के छोटे अंतराल में पूरे देश में सामूहिक रूप से 3.55 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। सभी केन्द्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए वर्ष 2023 में कुल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का सामूहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके फलस्वरूप इस अभियान के तहत कुल वृक्षारोपण की संख्या 5 करोड़ हो जाएगी, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति समग्र राष्ट्र के प्रयासों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अनुकरणीय योगदान को दर्शाता है। यह धरती माता के प्रति उनकी सच्ची कृतज्ञता का प्रतीक बनकर भी उभरेगा।

पर्यावरण को सुरक्षित रखने की मंशा देश के प्रत्येक नागरिक में सरकार ने जगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अभियान को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा पूरा किया जा रहा है। एक के बाद एक कई मुकाम हासिल किए जा रहे हैं। जहां बंजर भूमि थी, वहां भी जवानों ने अपनी मेहनत से हरियाली ला दी है। राजधानी दिल्ली से सटे अरावली की पहाड़ियों एनएसजी के जवानों ने समय-समय पर वृक्षारोपण किया है। आज यह क्षेत्र रमणीय बन चुका है।

खास बात यह है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान लद्दाख से कन्याकुमारी तक और भुज से अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सिरे तक विभिन्न प्रकार के पौधे लगा रहे हैं। सभी सीएपीएफ के दस लाख से अधिक जवानों ने, तीन वर्षों की अवधि में सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान के रूप में नागरिक समाज, शिक्षाविदों और स्कूली बच्चों सहित बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान किए हैं। इस अभियान में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से 18 अगस्त को महज एक दिन में ही छत्तीसगढ़ में चरम वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक दिवसीय मेगा वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। आईटीबीपी स्थानीय आबादी के सहयोग से राज्य के राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, नारायणपुर और कोंडागांव जिलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। छत्तीसगढ़ में एक दिन के दौरान आईटीबीपी इकाइयों द्वारा 20,000 से अधिक पौधे लगाए गए। उल्लेखनीय यह है कि देश भर में सीएपीएफ द्वारा 11 लाख से अधिक पौधे केवल एक ही दिन में लगाए गए।

वृक्षारोपण अभियान से बढ़ रहा हरियाली क्षेत्र

देश का कुल वन एवं वृक्ष आवरण क्षेत्र 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। 2019 में किए गए आकलन की तुलना में, देश के कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में 2,261 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। इसमें से वन आवरण में 1,540 वर्ग किमी और वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किमी की वृद्धि देखी गई है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ, वृक्षारोपण गतिविधियों में खाद्य असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और स्थानीय समुदायों की आजीविका असुरक्षा की बुराइयों से लड़ने की क्षमता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में, शीर्ष पांच राज्य मिजोरम (84.53%), अरुणाचल प्रदेश (79.33%), मेघालय (76.00%), मणिपुर (74.34%), और नागालैंड (73.90%) हैं। सत्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। इनमें से-लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 75% से अधिक वन क्षेत्र है, जबकि 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 33% से 75% के बीच वन क्षेत्र है। ■

पूरी दुनिया को दिया पर्यावरण संरक्षण का मंत्र

देश ही नहीं, पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कई बातें बताई हैं। जी20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक और उसके बाद शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत की ओर से पर्यावरण की बातें प्राथमिकता के आधार पर की गई है।

ब्यूरो

पर्यावरण की चिंता केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। भारत सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई योजनाएं देशव्यापी स्तर पर जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी तमाम जिम्मेदारियों के साथ ही पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। अपने कार्यकाल में जब भी विशेष अवसर आया है, प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर साथ आने की बात कही है। हाल ही में जब जी20 बैठक के दौरान पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ। हर मंच पर पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को पूरी दुनिया के सामने रखा है।

पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कई बातें बताई हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि दिल्ली घोषणा के साथ, जी20 देशों ने जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण के संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यों में 'तत्काल तेजी' लाने की प्रतिबद्धता जताई है। 28 जुलाई को चेन्नई में जी20 पर्यावरण और

जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक की वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज पर काम करने का आह्वान किया। सीधे तौर पर कहा कि मैं जी20 से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन पर रचनात्मक रूप से काम करने का आह्वान करता हूं।

प्रधानमंत्री ने लगभग दो हजार वर्ष पहले हुए महान कवि तिरुवल्लुवर का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि मेघ धरा से ग्रहण किए गए जल को बारिश के रूप में लौटाते नहीं है, तो महासागर भी सूख जाएंगे। प्रकृति और भारत में शिक्षण के नियमित स्रोत बनने के इसके तौर-तरीकों के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने एक और संस्कृत श्लोक को उद्धृत किया और समझाया न तो नदियां अपना पानी स्वयं पीती हैं और न ही पेड़ अपने फल खाते हैं। बादल भी अपने पानी से पैदा होने वाले अन्न को नहीं खाते हैं।

प्रधानमंत्री ने प्रकृति के लिए वैसे ही प्रावधान करने पर जोर दिया जैसे प्रकृति हमारे लिए करती है। धरती माता की रक्षा और देखभाल करना हमारी मौलिक जिम्मेदारी है और आज इसने 'जलवायु कार्रवाई' का रूप ले लिया है क्योंकि बहुत लंबे समय से कई लोगों द्वारा इस कर्तव्य को नजरअंदाज किया गया है।

भारत ने 2030 के लक्ष्य से नौ साल पहले गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित विद्युत क्षमता हासिल कर ली है। भारत आज स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के संदर्भ में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने भारत के लक्ष्य पर बात करते हुए कहा, हमने 2070 तक 'नेट जीरो' प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सीडीआरआई और 'उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह' सहित गठबंधनों के माध्यम से अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रखते हैं। गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप जंगल की आग और खनन से प्रभावित प्राथमिकता वाले परिदृश्यों में बहाली को पहचान रहे हैं।

भारत के पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु कार्रवाई को 'अंत्योदय' का अनुपालन करना चाहिए जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और विकास सुनिश्चित करना। यह देखते हुए कि 'ग्लोबल साउथ' के देश, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों से बहुत प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री ने 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन' और 'पेरिस समझौते' के तहत प्रतिबद्धताओं पर अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि ऐसा करना ग्लोबल साउथ की जलवायु-अनुकूल तरीके से विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। प्रतिनिधियों को सूचित किया, हमने 2070 तक नेट-शून्य प्राप्त करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री ने यह दोहराया कि हमें प्रकृति माता के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। विश्वास व्यक्त किया कि जी20 पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की यह बैठक उपयोगी और सफल सिद्ध होगी। प्रकृति माता किसी खंडित दृष्टिकोण को पसंद नहीं करती हैं बल्कि 'वसुधैव कुटुंबकम' - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य को प्राथमिकता देती है। ■

भारत के पारंपरिक ज्ञान के आधार पर, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि जलवायु कार्रवाई को 'अंत्योदय' का पालन करना चाहिए यानि हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करना होगा। विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देश जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों से प्रभावित हैं। हमें 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन' और 'पेरिस समझौते' के अंतर्गत निर्धारित प्रतिबद्धताओं के अनुरूप कार्रवाई की आवश्यकता है। यह वैश्विक दक्षिण को जलवायु अनुकूल तरीके से अपनी विकासात्मक आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करने में महत्वपूर्ण होगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अपनी संस्कृति से पहुंचे विरासत तक

ब्यूरो

संस्कृति सबको जोड़ती है। फिर चाहे संस्कृति भारत की हो या अन्य देश की। सांस्कृतिक जुड़ाव भी मकसद रहा है जी20 अभियान का। मूर्त विरासत न केवल भौतिक मूल्य की है, बल्कि किसी राष्ट्र का इतिहास और पहचान भी है। यह अभियान वसुधैव कुटुंबकम – 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना को समाहित करता है। यह अभियान सफलता पूर्वक आयोजित किया गया और आने वाले समय में इसके सकरात्मक परिणाम नजर आएंगे। इसके हर पड़ाव पर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सर्तकता और पैनी नजर रखी थी।

प्रधानमंत्री ने जी20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति मंत्रियों के जी20 समूह का काम पूरी मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति की अंतर्निहित क्षमता ही विविध पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण को समझने और एकजुट करने में सक्षम बना सकती है। उन्होंने देश की सांस्कृतिक संपदाओं और कलाकारों की राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर भी मैपिंग करने की बात कही। भारत की संस्कृति का जश्न मनाने के लिए कई केंद्रों के निर्माण का उल्लेख करते हुए, उन्होंने भारत के आदिवासी समुदायों की जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आदिवासी संग्रहालयों का उदाहरण दिया।

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। 'युगे युगीन भारत' राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा होने पर यह भारत के 5,000 वर्षों से अधिक के इतिहास और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बन जाएगा। इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने विरासत, आर्थिक विकास और विविधीकरण पर भी चर्चा की। असल में भारत का मंत्र 'विकास भी विरासत भी' यानी विकास के साथ-साथ विरासत का संरक्षण भी इसकी प्रतिध्वनि है। 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि जो भारतीय हस्तशिल्प की विशिष्टता को प्रदर्शित करता है और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देता है, प्रधानमंत्री ने कहा, 'भारत लगभग 3,000 अद्वितीय कलाओं और शिल्पों के साथ अपनी 2,000 साल पुरानी हस्तशिल्प विरासत पर गर्व करता है।' इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जी20 देशों द्वारा सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रयास समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और रचनात्मकता और नवाचार का समर्थन करेंगे। ■

भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है बी20

बिजनेस-20 (बी-20), वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ संवाद के लिए जी-20 का एक आधिकारिक मंच है। वर्ष 2010 में स्थापित, बी-20, जी-20 के सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है, जिसके प्रतिभागियों में कंपनियां और व्यापारिक संगठन शामिल हैं। बी-20 आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई करने योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। 25 से 27 अगस्त तक तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन की थीम आरएआईएसई (जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, दीर्घकालीन और न्यायसंगत व्यवसाय) रही। इसमें लगभग 55 देशों के 1,500 से

अमृतकाल के अमृत रक्षक

ब्यूरो

बीते नौ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने आचार-विचार और व्यवहार से एक नई छाप छोड़ी है। हर नागरिक को सम्मान देना और उनके सामर्थ्य की पहचान कराना उनकी खासियत रही है। हर उम्र, हर क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता इन्हीं कारणों से अधिक हो रही है। बात जब देश के युवाओं को रोजगार और सम्मान की आई, तो प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। साथ ही इन हजारों युवाओं को अमृत काल का अमृत रक्षक बताया।

28 अगस्त, 2023 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए थे। इस आयोजन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, जैसे- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), असम राइफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के साथ-साथ दिल्ली पुलिस में

रोजगार मेले का यह संस्करण ऐसे समय में हुआ है जब राष्ट्र गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में, हमने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए हैं। कानून के शासन द्वारा एक सुरक्षित माहौल विकास की गति को तेज कर देता है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

कर्मियों की भर्ती कर रहा है। पूरे देश से चुने गए नए रंगरूट केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत विभिन्न पुलिस बलों में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी), सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) और नॉन-जनरल ड्यूटी कैडर जैसे विभिन्न पदों पर भर्ती होंगे। प्रधानमंत्री ने नव नियुक्त अभ्यर्थियों को अमृत रक्षक इसलिए कहा क्योंकि उनके मुताबिक नव नियुक्त अभ्यर्थी न केवल देश की सेवा करेंगे, बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे।

प्रधानमंत्री ने रक्षा या सुरक्षा और पुलिस बलों में चयन के साथ-साथ आने वाली जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि सरकार सुरक्षा बलों की जरूरतों के बारे में बहुत गंभीर रही है। उन्होंने अर्धसैनिक बलों की भर्ती में बड़े बदलावों का उल्लेख किया। आवेदन से लेकर अंतिम चयन तक भर्ती की प्रक्रिया में तेजी आई है। पहले परीक्षाएं अंग्रेजी या हिंदी में होती थी, अब उनके स्थान पर 13 स्थानीय भाषाओं में भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मानदण्डों में ढील देकर सैकड़ों आदिवासी युवाओं की भर्ती का उल्लेख किया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष कोटा के बारे में भी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में सरकार के प्रयासों के कारण रूपांतरण का एक नया युग देखा जा सकता है। अवसंरचना के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले नौ वर्षों में केंद्र सरकार ने अवसंरचना पर ₹30 लाख करोड़ से अधिक व्यय किए हैं। इससे कनेक्टिविटी के साथ-साथ पर्यटन और आतिथ्य को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। ■

अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बी20 में भारत की प्राथमिकताओं और विश्व के लिए भारत की सिफारिशों समेत 7 सत्र आयोजित किए गए। कई वैश्विक और मास्टरकार्ड माइकल मिबाक के कार्यकारी अधिकारी और विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने भी बैठक में भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की अध्यक्षता के लिए 7 कार्यबल बनाए गए थे। व्यापक संरचनात्मक कार्यसूची पर फोकस करने और विचार विमर्श के लिए बी-20, भारत अफ्रीकी आर्थिक एकीकरण पर व्यापार में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के लिए 2 एक्शन परिषदों के माध्यम से कार्य कर रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विशेष सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन उत्तरदायित्व, त्वरित, नवोन्मेषण, निरंतरता और समानता के बारे में हैं, जो आज के बी-20 की विषयवस्तु हैं। बी-20 की विषयवस्तु 'आरएआईएसई' की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही 'आई' नवोन्मेषण का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह इनक्लूसिवनेस (समावेशिता) के एक और 'आई' को चित्रित करता है। उन्होंने बताया कि जी-20 में स्थायी सीटों के लिए अफ्रीकी संघ को आमंत्रित करते समय समान दृष्टिकोण लागू किया गया है। भारत का मानना है कि इस मंच के समावेशी दृष्टिकोण का इस समूह पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यहां लिए गए निर्णयों की सफलताओं का वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने और सतत विकास का सृजन करने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। ■

24 अगस्त की तारीख भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक हो गई है। शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान-3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय वैज्ञानिकों ने सॉफ्ट लैंडिंग कराई। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद के उस हिस्से पर उतरा, जहां आज तक कोई भी नहीं पहुंचा था। इस ऐतिहासिक पल का सीधा प्रसारण होने से पूरा देश चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर कदम रखने की ऐतिहासिक घटना का गवाह बना। उसके बाद देश ही नहीं, विदेशों से भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाइयों का तांता लग गया।

नए भारत का नया मुकाम

ब्यूरो

21 वीं सदी का भारत कई मायनों में केवल और केवल भारत का है। वर्ष 2023 को लेकर तो किसी को जरा भी शंका नहीं कि भारत दुनिया के उन्नत देशों में शुमार हो रहा है। चाहे जी20 की अध्यक्षता हो या अंतरिक्ष का असीम क्षेत्र। देश ने हर जगह अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बीते दशकों में पृथ्वी से लाखों किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रमा के रहस्यों को सुलझाने की कई कोशिशें हुईं। कई यान चंद्रमा की सतह पर उतरे। मगर, भारत ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का जो रिकॉर्ड कायम किया है, वह दुनिया में पहला है। अब तक किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम नहीं रखा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यह कमाल कर दिया है।

इसरो की इस उपलब्धि पर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। उल्लेखनीय है कि 24 अगस्त की शाम भारत जब अंतरिक्ष विज्ञान में इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने चंद्रयान 3 को लैंडिंग कराने में सफल रहा, तो सबसे पहले इसकी औपचारिक सूचना इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पूरी दुनिया को दी। उन्होंने कहा, इंडिया ऑन द मून!

इसके चंद मिनट बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इसमें उन्होंने इसरो प्रमुख एस. सोमनाथ की सराहना की। अनेक विश्व नेताओं ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें एक्स पर उत्तर देते हुए उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है।

> **चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा का अभिनंदन करता हूं।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

प्रधानमंत्री ने इसरो की कड़ी मेहनत की जानकारी देशवासियों तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के दक्षिणी हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। इसरो ने अपनी अनुसंधान सुविधा में एक कृत्रिम चंद्रमा तक बना डाला। प्रधानमंत्री ने इस तरह के अंतरिक्ष मिशनों की सफलताओं को भारत के युवाओं में नवाचार और विज्ञान के प्रति उत्साह भरने का श्रेय दिया। आज भारत के बच्चों के बीच चंद्रयान का नाम गूंज रहा है। हर बच्चा वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है।

दरसअल, 'चंद्रयान' भारत की महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना रही है। भारतीय वैज्ञानिक चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना

चाहते हैं। वर्ष 2003 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चांद से जुड़े मिशन की घोषणा की थी। इसरो ने वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 लॉन्च किया। वह डीप स्पेस में भारत का पहला मिशन था। वर्ष 2019 में चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान-2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा इसरो ने चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। चंद्रयान-3 में प्रपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर लगे थे। चंद्रयान-3 का लैंडर+रोवर चंद्रयान-2 के लैंडर+रोवर से करीब 250 किलो ज्यादा वजनी है। चंद्रयान-2 की मिशन लाइफ 7 साल (अनुमानित) थी, वहीं चंद्रयान-3 के प्रपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने काम करने के लिए डिजाइन किया गया।

एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया था कि चंद्रयान-3 ने कम लागत के अंतरिक्ष अभियानों में भारत की क्षमता सिद्ध की। हमने अपने कौशल से ऊंची लागत की पूर्ति करना सीख लिया है। अनुसंधान एवं विकास प्रयासों में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 'अनुसंधान-राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन' विधेयक लेकर आए, जिसे संसद के पिछले सत्र में लोकसभा द्वारा पारित किया गया और जिसमें पांच वर्षों के लिए ₹50 हजार करोड़ का बजट था। जब इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा, तो यह बड़ा गेम-चेंजर होगा।

जब पूरा देश वैज्ञानिकों के कठिन मेहनत और उनके प्रयासों की सराहना कर रहा था, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने भी जमकर प्रशंसा की। अपने वीडियो संदेश में केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का भारत के स्पेस मिशन की कल्पना के लिए नई अंतरिक्ष नीति लाने के लिए आभार प्रकट किया। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाला अमृत काल अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भारत के भविष्य के लिए मंगलकारक है और आज का चंद्रयान-3 मिशन इसका द्योतक है। सरकार की नई स्पेस पॉलिसी के तहत पिछले एक दशक में 55 स्पेसक्राफ्ट और 50 लॉच व्हीकल मिशन चलाए गए। साथ ही भारत ने एकसाथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया, भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना और चंद्रयान-3 मिशन को भी सफलता मिली है। सरकार द्वारा 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों से प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिला है और इससे हमारे मिशन को गति मिलेगी। ■

विशेष बातें

- अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की लगभग 20 परिक्रमाएं कीं और प्रत्येक परवलय (पैराबोला) में वह तब तक ऊपर उठा, जब तक कि वह बाहर निकल कर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के नियन्त्रण में नहीं पहुंच गया और निर्धारित स्थान पर उतरने से पहले उसने चंद्रमा की 70-80 परिक्रमाएँ भी कीं।
- रूसी चंद्रमा मिशन, जो असफल रहा था, की लागत करीब ₹1,600 करोड़ थी, वहीं चंद्रयान-3 मिशन की लागत लगभग ₹600 करोड़ थी।
- चंद्रमा और अंतरिक्ष मिशन पर आधारित हॉलीवुड फिल्मों की लागत भी ₹600 करोड़ से अधिक होती है।
- चंद्रयान-3 का लैंडर जिस स्थान पर उतरा था, उसे अब 'शिव शक्ति' के नाम से जाना जाएगा।
- चंद्रमा की सतह पर वह स्थान जहां चंद्रयान-3 ने अपने निशान छोड़े हैं, उसे 'तिरंगा' के नाम से जाना जाएगा।
- चंद्रयान-3 की सफलता में हमारी महिला वैज्ञानिकों, देश की नारी शक्ति की बड़ी भूमिका रही है।
- 'तीसरी पंक्ति' से 'पहली पंक्ति' तक की यात्रा में, हमारे 'इसरो' जैसे संस्थानों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है।
- हर वर्ष, 23 अगस्त का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

सबकी सहभागिता 'अमृत वाटिका'

'मेरी माटी मेरा देश अभियान' की सफलता की कामना है। आशा है कि देशभर से जमा की गई मिट्टी से तैयार होने वाली 'वाटिका' 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के आदर्श को साकार करेगी।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ब्यूरो

अब तक देश ने कई प्रकार की कलश यात्राओं को देखा और समझा है। केंद्र सरकार की पहल और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान चल रहा है। महानगर हो, शहर हो, कस्बाई नगर हो या हो गांव। हर जगह से 'अमृत कलश यात्रा' निकल रही है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर निकल रही इस अनूठी यात्रा के जरिए शहीदों को याद किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा था 'विविधता भी एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम करती है। अमृत महोत्सव की गूंज और 15 अगस्त के आह्लाद के समय में हमारे वीर शहीद पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान शुरू किया गया है। अमर शहीदों की याद में देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।' अपने पहले चरण में, अभियान ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2.33 लाख से अधिक स्मारक पट्टिकाएं बनाई गईं, जिन्हें 'शिलाफलकम' के नाम से जाना जाता है। पंच प्राण प्रतिज्ञा, पहल की एक और आधारशिला है, जिसमें करीब चार करोड़ प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिज्ञाएं ऑनलाइन अपलोड कीं। इसके अलावा, देश की सेवा करने वाले बहादुरों को सम्मानित करने के लिए दो लाख से अधिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए। वसुधा वंदन थीम के तहत, 2.36 करोड़ से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए गए, और प्रभावशाली 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं (पवित्र उद्यान) स्थापित की गईं।

भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। प्रधानमंत्री ने 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान का सुझाव देते हुए कहा था कि इसकी टैगलाइन 'मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन' है। अभियान वेबसाइट के अनुसार, 'राष्ट्रव्यापी अभियान राष्ट्र और बहादुरों की उपलब्धियों को जश्न मनाने को लेकर है।' इस वर्ष यह अभियान गांव, पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके 'जनभागीदारी' को बढ़ावा देने के लिए है।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि अभियान का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अभियान 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के उनके दृष्टिकोण को दोहराते हुए, देश को एकजुट करने में प्रगति करेगा।

जैसे-जैसे अभियान अपने दूसरे चरण में आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत में हर घर तक गतिविधियों का विस्तार करते हुए इसे और भी व्यापक पहुंच बनाने की योजना है। दूसरे चरण में अमृत कलश यात्राएं शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से एकत्रित मिट्टी और चावल के दानों से भरे पवित्र बर्तनों को ले जाने वाला एक जुलूस है। ये बर्तन या कलश, अंततः एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। ■

राष्ट्र सेवा में जीवन समर्पित

भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने उनकी समाधि 'सदैव अटल' जाकर पुष्पांजलि अर्पित की।

ब्यूरो

कुछ लोग असामान्य व्यक्तित्व के धनी होते हैं। वह सिद्धांत, विचार एवं व्यवहार की सर्वोच्च चोटी पर रहते हुए सदैव जमीन से जुड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तित्व से ओत-प्रोत थे अटल बिहारी वाजपेयी। तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त को पुण्यतिथि थी। भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर जाकर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि 'सदैव अटल' पर 16 अगस्त को प्रार्थना सभा आयोजित की गई।

भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी , केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहित सरकार के कई केंद्रीय मंत्री और प्रबुद्ध लोगों ने 'सदैव अटल' जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। इससे पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने दिवंगत नेता की स्मृति में आयोजित एक प्रार्थना सभा में भी भाग लिया।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पांचवीं पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय राजनीति के अजातशत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा व सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए। राष्ट्रसेवा की अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी तो दूसरी ओर उन्होंने पोखरण से पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय कराया। अपने संगठन कौशल से पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे युग पुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिश: नमन।

पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने उनकी समाधि 'सदैव अटल' जाकर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि भारतीय राजनीति के अजातशत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा व सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए।

भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर पर नजर डालने पर मालूम चलता है कि वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में 1968-1973 तक इसके अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी की देशभर में उनकी लोकप्रियता का ही नतीजा था कि वे चार दशक तक भारतीय संसद के सदस्य थे। वे इकलौते राजनेता थे, जिन्होंने चार राज्यों की छह लोकसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए अटल जी ने कई इतिहास रचे हैं। उन्होंने 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' का नारा दिया। जब देश के विकास की गाथा पर चर्चा होगी, तो भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम प्रमुखता से लिया जाएगा। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि उनके नेतृत्व से भारत बहुत लाभान्वित हुआ। सही मायने में उन्होंने देश को प्रगति पथ पर बढ़ाने और कई क्षेत्रों में इसे 21वीं सदी में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ■

अंतरिक्ष क्षेत्र देश की महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाईयों पर ले जाएगा

सरकार की नई स्पेस पॉलिसी के तहत पिछले एक दशक में 55 स्पेसक्राफ्ट और 50 लॉच व्हीकल मिशन चलाए गए, भारत ने एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया, भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना और आज चंद्रयान-3 मिशन को भी सफलता मिली है।

> **देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई। आजादी के अमृत काल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को बधाई देता हूं। आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है।**
>
> **श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

ब्यूरो

इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की सफलता पर आम और खास, हर भारतीय खुशी से झूम रहा था। सभी वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे और साथ ही केंद्र सरकार की प्रशंसा कर रहे थे कि सरकार ने वैज्ञानिकों का पूरा साथ निभाया। सरकारी स्तर पर कहीं कोई कमी नहीं होने दी। सरकार की नजर चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल तरीके से उतरने तक बनी रही।

जब पूरा देश वैज्ञानिकों की कठिन मेहनत और उनके प्रयासों की सराहना कर रहा था, तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने भी जमकर प्रशंसा की। अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि जिस अंदाज से पूरा विश्व चंद्रयान-3 की सफलता को देख रहा है, यह अंतरिक्ष में भारत का युग है। मैं इस सफलतम अभियान के लिए इसरो और हमारे वैज्ञानिकों के अडिग प्रयासों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रयान-3 ने लंबी छलांग लगाकर देश को चार देशों के विशिष्ट क्लब में पहुंचा दिया है। उसने चांद की अनछुई सतह पर उतरकर भारत को ऐसा करने वाला पहला देश बनाया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई। आजादी के अमृत काल में हमारे देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो हम सबके लिए गौरव का विषय है। टीम चंद्रयान के सभी वैज्ञानिकों और सभी इंजीनियरों को बधाई देता हूं। आपके प्रयास ने देश को विश्व में गौरव दिलाया है। चंद्रयान के चंद्रमा पर लैंड करते ही लोग झूम उठे और उन्होंने पटाखे फोड़ कर जश्न मनाया।

अपने वीडियो संदेश में केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का भारत के स्पेस मिशन की कल्पना के लिए नई अंतरिक्ष नीति लाने के लिए आभार प्रकट किया। गृह मंत्री ने कहा कि आने वाला अमृतकाल अंतरिक्ष के क्षेत्र में और भारत के भविष्य के लिए मंगलकारक है और आज का चंद्रयान-3 मिशन इसका द्योतक है। सरकार की नई स्पेस पॉलिसी के तहत पिछले एक दशक में 55 स्पेसक्राफ्ट और 50 लॉच व्हीकल मिशन चलाए गए। साथ ही भारत ने एकसाथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड बनाया, भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बना और चंद्रयान-3 मिशन को भी सफलता मिली है। सरकार द्वारा 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों से प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिला है और इससे हमारे मिशन को गति मिलेगी। ■

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का डंका

15वें ब्रिक्स शिखर सम्मलेन में आमंत्रित नेताओं ने वैश्विक आर्थिक सुधार, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ साझेदारी सहित महत्वपूर्ण चर्चा की और ब्रिक्स एजेंडे पर अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ-साथ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भाग लिया।

ब्यूरो

जब शब्दों को व्यापक और गहरे अर्थों में समझाया जाए, तो शब्द के अर्थ की गहराई समझ में आती है। वैसे तो ब्रिक्स का अर्थ है 5 देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स को नवीन अर्थ में समझाया है। इसमें बी- ब्रेकिंग बैरियर्स (बाधाओं को तोड़ना), आर- रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज (अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करना), आई- इंस्पायरिंग इनोवेशन (प्रेरक इनोवेशन), सी- क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी (अवसर पैदा करना) और एस- शेपिंग द फ्यूचर (भविष्य को आकार देना)। 23 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें आमंत्रित नेताओं ने वैश्विक आर्थिक सुधार, अफ्रीका और ग्लोबल साउथ के साथ साझेदारी सहित महत्वपूर्ण चर्चा की और ब्रिक्स एजेंडे पर अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ-साथ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने भाग लिया। श्री नरेन्द्र मोदी ने भी भागीदारी दर्ज कराई। यहीं बात थमी नहीं, उन्होंने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का आह्वान किया और अफ्रीका के साथ भारत की घनिष्ठ साझेदारी को रेखांकित किया। साथ ही एजेंडा 2063 के तहत अफ्रीका को उसकी विकास यात्रा में सहयोग करने संबंधी भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। वैश्विक संस्थानों को प्रतिनिधिक और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उनमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ जंग, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संबंधी पहल, साइबर सुरक्षा, खाद्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग का आग्रह किया।

> **अपनी प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों को मजबूत करने के अलावा, हमें अपनी मूल्य प्रणालियों में नैतिकता और ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।**
>
> **श्री नरेन्द्र मोदी**
> **प्रधानमंत्री**

श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, आपदा निरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, वन अर्थ वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस और पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र जैसी अंतरराष्ट्रीय पहल का हिस्सा बनने के लिए भी देशों को आमंत्रित किया और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक को साझा करने की भी पेशकश की। इसके कई पहलुओं पर 15 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रकाश डाला। उन्होंने यूएनएससी सुधारों के लिए निश्चित समयसीमा तय करने का आह्वान किया, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में सुधार का आह्वान किया, डब्ल्यूटीओ में सुधार का आह्वान किया, ब्रिक्स से अपने विस्तार पर आम सहमति बनाने का आह्वान किया, ब्रिक्स से ध्रुवीकरण नहीं बल्कि एकता का वैश्विक संदेश भेजने का आग्रह किया, ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया, ब्रिक्स भागीदारों को इंडियन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर-भारतीय स्टैक की पेशकश की गई, ब्रिक्स देशों के बीच स्किल मैपिंग, कौशल और गतिशीलता को बढ़ावा देने का उपक्रम प्रस्तावित, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत चीतों के संरक्षण के लिए ब्रिक्स देशों के संयुक्त प्रयासों का प्रस्ताव, ब्रिक्स देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा का भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव और ब्रिक्स साझेदारों से जी20 में एयू की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने का आह्वान किया। ■

नागरिकों को मिले न्याय और सुरक्षित हों उनके संवैधानिक अधिकार

ब्यूरो

सुरक्षा सिर्फ बयानबाजी से नहीं आती। इसके लिए किसी को आगे आना होता है। यदि सब अपनी-अपनी सुरक्षा की सोचेंगे, तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? देश में सुरक्षा के कई मामले लंबित हैं। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं को मजबूत कर राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। इस बाबत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2023 का उद्घाटन करते हुए शीर्ष पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे जांच में वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग बढ़ाएं। उन्होंने सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन में जिलास्तरीय पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया।

इस सम्मेलन में देश भर के शीर्ष अधिकारियों तथा विषय-विशेषज्ञों सहित 750 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन हिस्सा लिया। दिल्ली से इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री सहित, केंद्रीय गृह सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व संभाल रहे अनेक वरिष्ठ अधिकारी, डिप्टी एनएसए, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफएस) के महानिदेशक शामिल हुए। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व श्री शाह ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सेवा कार्य के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सम्मेलन के पहले दिन, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। इनमें भारत में टेरर एंड नार्को फाइनांसिंग संबंधी रुझान, जांच में फॉरेंसिक का उपयोग, सामाजिक चुनौतियां, न्यूक्लियर व रेडियोलॉजिकल आपात स्थिति के लिए तैयारियां तथा साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसे विषय शामिल थे।

मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री शाह ने देश तथा नागरिकों से संबंधित अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों से भी निपटने का आश्वासन दिया। इस क्षेत्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्होंने सभी राज्यों और एजेंसियों से आग्रह किया कि वे ड्रग डीलरों और नेटवर्कों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखें। समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री शाह ने नागरिकों को समय से न्याय दिलाने और यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार अनिवार्य रूप से मिले। उन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने में एक क्रांतिकारी रुख अपनाने का सुझाव देते हुए पुलिस व्यवस्था में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कांस्टेबल से लेकर उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों के स्तर पर समान रूप से किया जाना चाहिए। उन्होंने संसद में नए कानून पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए संपूर्ण आपराधिक न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस कड़ी में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि जब संसद द्वारा नए कानून पारित किए जाएं तो उन्हें आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री अमित शाह ने जांच तथा अभियोजन की पूरी प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए नवगठित आपराधिक न्याय व्यवस्था की भविष्य की मांग के अनुसार पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की नई पहलों को भी सूचीबद्ध किया।

सत्र के समापन पर उन्होंने सम्मेलन में मौजूद सभी प्रतिभागियों से कहा कि अगले 25 वर्षों में कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी 2047 तक भारत अग्रणी देश बन पाएगा। नतीजतन प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी का सपना साकार हो पाएगा। साथ ही उन्होंने अन्य दूसरे देशों से सीख लेने के महत्व का सुझाव देते हुए प्रतिभागियों से अगले 25 वर्षों में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, ताकि अन्य देश भी हमसे कुछ सीख सकें। ■

सेवा के जरिए संकल्प सिद्धि

यदि देश की प्रगति की भावना से राजकाज हो, तो प्रगति हर ओर दिखती है। इस दिशा में देश के सभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जुटे हुए हैं। फिर काम चाहे एकता का हो, विकास का हो या रोजगार का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मंत्रालय के सभी राज्य मंत्री देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए समर्पित हैं।

ब्यूरो

गत 31 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने पटना में सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस त्योहार में उनके साथ एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

28 अगस्त को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार मेले के आठवें चरण में 51,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने भी भाग लिया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के छावला में बीएसएफ शिविर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस

बलों (सीएपीएफ) और दिल्ली पुलिस के लिए उम्मीदवारों की भर्ती पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के बाद से रोजगार के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप देश भर में बड़ी संख्या में रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर पैदा हुए।

इस प्रयास का उद्देश्य एक वर्ष के भीतर दस लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। यह आने वाले समय में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने सभी नवनियुक्त उम्मीदवारों और उनके माता-पिता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं। साथ ही राष्ट्र की सेवा के लिए उनके समर्पण की सराहना की।

28 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय प्रमाणिक गंगटोक में भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) द्वारा आयोजित रोजगार मेले के 8वें चरण में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार के 104 नवनियुक्त उम्मीदवारों ने नियुक्ति पत्र प्राप्त किए। यह पहल देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

31 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार टाउन हाई स्कूल के उत्साही एनसीसी कैडेटों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।

18 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा ने चेन्नई में रेप्को बैंक और रेप्को माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दो योजनाओं का शुभारंभ किया। यह योजनाएं हैं- रेप्को थंगामगल (एक जमा योजना) और रेप्को वृक्ष (एक सूक्ष्म वित्त ऋण योजना)। इसके अलावा उन्होंने सिलाई मशीनों का वितरण किया, जिससे व्यक्तियों को स्व-रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इससे वे सशक्त बनेंगे।

17 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा ने चेन्नई में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) क्षेत्रीय केंद्र में नवनिर्मित पारिवारिक क्वार्टरों का उद्घाटन किया। इससे एनएसजी कर्मियों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ■

नई आशा जगाता है अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान

भूपेंद्र यादव

एलवायु परिवर्तन ने मानव के श्रेष्ठता भाव को तोड़ा है। आविष्कार और नव-प्रवर्तन करने में सक्षम मस्तिष्क से संपन्न मानव ने खुद को प्रकृति की अन्य सभी रचनाओं से न केवल अलग, बल्कि उनसे श्रेष्ठ भी माना। यही सोच मानव पर हावी हुई है, जिसने लालच का रूप ले लिया। फलस्वरूप लोग प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करने लगे। पेड़ों को काटने लगे और नदियों को प्रदूषित करने लगे। यह दोहन मानव ने इस सोच से प्रेरित होकर किया कि प्रकृति में उपलब्ध हर चीज मानव के उपभोग के लिए बनी है। पर जलवायु परिवर्तन और इसके कारण पैदा हुई अनिश्चितताओं ने यह साबित किया की मनुष्य प्रकृति पर वैसे ही निर्भर है जैसे प्रकृति मनुष्य पर` पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदर्श वाक्य में इस व्यावहारिक दर्शन को खूबसूरती से समाहित किया गया है – प्रकृति रक्षति रक्षित: (प्रकृति तभी रक्षा करती है, जब उसकी रक्षा की जाती है)।

एडुआर्डो कोह्न की पुस्तक 'हाउ फॉरेस्ट थिंक' इस बात की बहुत वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करती है कि प्रकृति के तत्व अपनी सोच के आधार पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कोह्न लिखते हैं कि इक्वाडोर के जंगलों और उसके आसपास रहने वाले लोग मुंह ऊपर करके सोते हैं, ताकि अगर कोई जगुआर आए, तो वह उन्हें देख ले और वापस चले जाए। लोगों का मुँह ऊपर देखकर जगुआर को लगता है कि सोया हुआ व्यक्ति उसे देख सकता है यदि वे मुंह नीचे करके सोते हैं, तो जगुआर सोचता है कि वे उसे नहीं देख सकते हैं और यह भोजन बन सकते हैं। यदि एक जगुआर लोगों को पीछे मुड़कर देखने में सक्षम देखता है, तो वह उन्हें अकेला छोड़ देगा। यदि वह लोगों को शिकार के रूप में देखे, तो उन पर हमला कर देगा।

कोह्न का तर्क है कि पेड़ भी सोच सकते हैं। उनका कहना है कि विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट पेड़ों का उगना आकस्मिक नहीं है। पेड़ अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, क्योंकि उनमें विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। कोह्न हमें अपने पर्यावरण के प्रति 'अनभिज्ञ' होने के प्रति आगाह करते हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान पर्यावरण जागरूकता का एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। 12 जुलाई, 2020 को शुरू की गई, इस पहल की सबसे सराहनीय बात यह है कि इसमें हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों की प्रबल भागीदारी है। सीएपीएफ कर्मियों की 'प्रकृति योद्धाओं' के रूप में भागीदारी पूरी परियोजना में विश्वसनीयता और अभूतपूर्व समर्पण की एक अनूठी परत जोड़ती है।

12 जुलाई, 2020 को शुरू की गई, इस पहल की सबसे सराहनीय बात यह है कि इसमें हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों की प्रबल भागीदारी है। सीएपीएफ कर्मियों की 'प्रकृति योद्धाओं' के रूप में भागीदारी पूरी परियोजना में विश्वसनीयता और अभूतपूर्व समर्पण की एक अनूठी परत जोड़ती है।

हो सकता है शुरूआत में यह सहयोग असामान्य लगे। लेकिन इसका उद्देश्य तब स्पष्ट हो जाता है, जब कोई उन विविध इलाकों के बारे में विचार करता है, जहां हमारे पुलिस बल तैनात हैं। पारिस्थितिक रूप से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से कुछ में तैनात, वे पर्यावरणीय गिरावट के प्रभावों के प्रत्यक्ष गवाह हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी निश्चित रूप से इस पहल में अद्वितीय समृद्धि और समझ लाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस ऐतिहासिक पहल की सराहना करता है। इस पहल का लक्ष्य पूरे भारत में पांच करोड़ से अधिक पौधे लगाना है। यह हरित आवरण को बढ़ाने, जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के हमारे लक्ष्यों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। पांच करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित करके, विशेष रूप से वनों की कटाई और शहरीकरण के बोझ वाले क्षेत्रों में, सीएपीएफ का योगदान वन संरक्षण में हमारे राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ाता है। इस पहल की प्रतिभा इसके समावेशी दृष्टिकोण में समाहित है। उन्हें हरित क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है, चाहे प्रत्यक्ष भागीदारी के माध्यम से या समर्थित कार्यक्रमों के माध्यम से।

सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। एक स्थायी पर्यावरण के निर्माण में हमारे सामूहिक प्रयासों को तब बल मिलेगा जब प्रत्येक नागरिक कार्रवाई के इस आह्वान पर ध्यान देगा। यह हर्ष का विषय है कि कई सरकारी विभाग पहले से ही वृक्षारोपण के इस पावन काम में लगे हुए हैं। मेरा विश्वास है कि अन्य विभाग तथा संस्थान भी सीएपीएफ द्वारा स्थापित उदाहरण का अनुकरण करेंगे। ■

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन एवं श्रम व रोजगार, मंत्री हैं)

1 अगस्त को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में ब्यूरो की ओर से प्रकाशित पुस्तिका 'पुलिस विज्ञान' का विमोचन किया गया। इस अवसर पर ब्यूरो एवं एनसीआरबी द्वारा आयोजित अंतर कार्यालय प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया।

28 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा ने श्रीगंगानगर में प्रधानमंत्री रोजगार मेला के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए।

14 वीं एनडीआरएफ टीम ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में शिव मंदिर समर हिल में हुए भूस्खलन के बाद एसएआर ऑपरेशन चलाया। एनडीआरएफ की टीमों के अथक और कठिन प्रयासों से 15 अगस्त से 24 अगस्त 2023 के बीच घटना स्थल से 12 शव निकाले।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 'पुलिस और सेवा' अभियान के तहत आपदा रक्षा सर्वदा अभ्यास सत्र 'रोप रेस्क्यू' का आयोजन हिमाचल प्रदेश के ऊना, सिरमौर, कुल्लु और चंबा जिलों में किया गया।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

देश की संस्कृति और साहित्य में कई संदर्भ पेड़ों और जंगलों के महत्व को बताते हैं। प्रकृति और प्रगति को एक साथ लाना 'न्यू इंडिया' के विकास मॉडल की पहचान रही है। हम सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहे हैं, लेकिन हम जलवायु संबंधी प्रतिबद्ध लक्ष्यों को पूरा करने वाले संभवतः एकमात्र प्रमुख देश भी रहे हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037